खण्ड-118, अंक-6
शनिवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(21 फरवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 118 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
४ मई १९५३
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ फ़रवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०१)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री

जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री

मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफिज श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर , श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री

शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी,श्रीमती
संग्राम सिंह,श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी,श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी श्री,
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमानखां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष— एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने भेजा है मैं उसको हाउस के सामने पढ़ता नहीं हूं क्योंकि इसके विशेष कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। वह खुद जानते हैं कि इस तरह की मामूली बातें इन्तजाम के मामले में आती रहती हैं। इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ का आय-व्यय-क

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)— जनाबवाला, मैं उत्तर प्रदेश का सन् १९५३–५४ ई० का बजट पेश करता हूं।

२–मुझको बड़ी खुशी है कि मुझे भारत के सब से बड़े राज्य का—जो सिर्फ़ आबादी में ही बड़ा नहीं है, बल्कि उसकी आमदनी और खर्च भी हर दूसरे राज्य से अधिक हैं—आगामी साल के लिए बजट इस सदन के सामने पेश करने की खुशनसीबी हासिल हो रही है। मेरी यह खुशी और भी बढ़ जाती है जब मैं यह देखता हूं कि मैं जिस राज्य का बजट पेश कर रहा हूं वह स्वतन्त्र भारत का एक कल्याणकारी राज्य है।

३–डिमोक्रेसी या जनतन्त्र में एक राज्य का वेलफ़ेयर राज्य होना ज़रूरी है। जो राज्य अपना कर्त्तव्य सिर्फ़ जान-माल की हिफ़ाज़त या चौकसी तथा अमन व शान्ति की बरक़रारी तक महदूद रखता है वह वेलफ़ेयर राज्य नहीं है। वेलफ़ेयर राज्य का कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी जनता के लिए हर तरह की उन्नति और तरक्क़ी के मौक़े पैदा कर दे और इसका ज़िम्मेदार बने कि उसके हर फ़र्द या व्यक्ति को इस से फ़ायदा उठाने में कोई चीज़ रोकने वाली न हो। उस हुकूमत पर जिसका मक़सद वेलफ़ेयर राज्य क़ायम करना हो, विकास या डेवलपमेंट का प्रबन्ध करना और ज़रूरी उन्नतियों के सामान इकट्ठे कर देना भी वाजिब है। उत्तर प्रदेश सन् १९४६ से अब तक इस अभिप्राय या मक़सद को बराबर सामने रखता रहा और हालात के मातहत जहां तक सम्भव हुआ वेलफ़ेयर स्टेट बनने की तरफ़ बराबर क़दम बढ़ाता रहा है। इसका हाल, उस वक्त से लेकर अब तक जो बजट बनते आये हैं, और इस बजट से भी जो आज पेश किया जा रहा है, मालूम हो सकता है, चूंकि बजट वह आइना होता है जिसमें उसको बनाने वाली सरकार का पूरा रूप दिखायी देता है। एक ऐसे देश में जिसका और जिसके अन्दर रहने वालों की बहुमत का ख़ास सम्बन्ध खेती से रहा हो और खेती उसकी आर्थिक स्थिति की जान रही हो, सन् १९४६ से लेकर अब तक सोलह लाख पांच हज़ार एकड़ ऐसी ज़मीन के लिए, जो पहले सिंचाई नहीं पाती थी, सरकार की ओर से सिंचाई का प्रबन्ध हुआ हो, जहां दस हज़ार दो सौ बासठ मील पक्की व कच्ची सड़कें बनी हों, जहां चौदह हज़ार दो सौ पंचानबे स्कूल और कालेज स्थापित हुए हों, जहां सन् १९४६ से अब तक बाइस लाख इक्कानबे हज़ार एकड़ नयी ज़मीन जोत में लायी गयी हो, जहां सात लाख टन ग़ल्ले के अधिक उपजाव का मुस्तक़िल इन्तज़ाम हो चुका हो, जहां उम्दा बीज मिलने, मवेशी की नस्लों को तन्दुरुस्त और मुफ़ीद बनाने का बराबर बन्दोबस्त होता रहा हो, जहां अब तक अलावा पहले बने हुए ट्यूब-वेलों के ७६६ ट्यूब-वेल बन चुके हों, और वो हज़ार मील आबपाशी की चैनल खुद चुकी हों, जहां १९५०–५१ के ख़त्म तक नगवा, खजुरी, हरई डैम बनकर आबपाशी होने लगी हो, ललितपुर डैम, सप्रार डैम, कबरई डैम और बेलन कैनाल का वीयर (weir) जैसी चीज़ मुकम्मल हुई हो और कितने ही डैमों के ऊपर काम हो रहा हो, जहां चौदह लाख एकड़ बंजर ज़मीन को तुड़वा कर कृषि के क़ाबिल बनाया गया हो, जहां दो सौ चौरासी शफ़ाख़ाने खोले गये हों, टी० बी० क्लिनिक खुले हों, मलेरिया को नापैद करने की योजना जारी की गयी हो, इंडस्ट्री और विशेषकर काटेज इंडस्ट्री की हिफ़ाज़त और तरक्क़ी का प्रबन्ध हुआ हो, बिजली की बढ़ोत्तरी के लिए पावर हाउस बन रहे हों, और तीन हज़ार नब्बे किलोवाट का गोरखपुर पाइलेट पावर-स्टेशन, जहां सोहावल पावर स्टेशन पर दो हज़ार किलोवाट का और इन्तज़ाम हुआ हो और नौ हज़ार तीन सौ किलोवाट बिजली देने वाला मोहम्मदपुर पावर स्टेशन बना हो ; बस्ती, ख़लीलाबाद, देवरिया और चौरीचौरा को बिजली मिली हो और जहां मज़दूरों की मज़दूरियां क़ानून के द्वारा मुक़र्रर हो रही हों, उनके लिए बेहतर मकानों का इन्तज़ाम हो रहा हो, मालिकों और मज़दूरों के ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने की तदबीरें हो रही हों, और इसी तरह के और कितने ही काम आम फ़ायदे के हो रहे हों और जो राज्य सन् १९४६ से अब तक दो अरब सैंतालीस करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हज़ार नौ सौ रुपये ख़ालिस विकास के कामों पर ख़र्च कर चुका हो उसकी बाबत अगर यह कहा जाये कि वह बराबर वेलफ़ेयर स्टेट की हैसियत से उन्नति कर रहा है और एक दिन यक़ीनन पूर्ण वेलफ़ेयर स्टेट बन जाने वाला है और उसमें आज जो कमियां हैं वह कल पूरी होने वाली हैं, तो कुछ बेजा नहीं।

४–जो कुछ इस वक्त तक हुआ है, वह सस्त गिरानी, ज़रूरी सामानों और साधनों की कमी, ट्रांस्पोर्ट की दिक्क़त और कुछ अर्स से रुपये की कमी की हालत में हुआ है और उस मुल्क में हुआ है जिसको आज अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह चीज़ और वह चीज़ बाहर से मंगानी पड़ती है। इस बजट को जो मैंने इस वक्त पेश किया है अगर इस नज़र से देखा जाय कि इसमें क्या है तो मालूम होगा कि इसमें जान-माल की हिफ़ाज़त के अलावा, काश्तकार, मज़दूर, कारीगर, लिख-पढ़े, अनपढ़, शहरी, देहाती सभी के लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध है। तन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य की हिफ़ाज़त, शिक्षा, अमन या शांति, आने जाने के रास्ते, खेती-बाड़ी की तरक्क़ी, सिंचाई

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

और बिजली की बढ़ोत्तरी, इन्डस्ट्री और काटेज इन्डस्ट्री के प्रबन्ध, उन चीजों के अतिरिक्त मौजूद हैं जो बजट में हैं और मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं। अगर और ज्यादा तफ़सील से देखना हो तो बजट के साल में जो होने वाला है, इसमें सिंचाई का बढ़ाया जाना जारी रहेगा और बढ़ोत्तरी की रफ्तार तेज कर दी जायगी। छः सौ पचास नये ट्यूब-वेल लगेंगे ; पांच सौ मील सिंचाई की चैनल बनेंगी ; दो नये डैम, रंगवां और अहरौरा अन्तिम रूप से तैयार हो जायेंगे और उनसे सिंचाई के लिए पानी देना शुरू कर दिया जायगा और तीन लाख पचास हज़ार एकड़ जमीन को सिंचाई मिलने लगेगी। चन्द्रप्रभा, अर्जुन, माताटीला बांधों और बेलन कैनाल वग़ैरह के काम और ज्यादा तेजी से होंगे। कृषि में एक लाख पच्चीस हज़ार एकड़ बंजर जमीन तोड़ कर उसको खेती के क़ाबिल बना दिया जायगा ; पचास हज़ार एकड़ जमीन के सम्बन्ध में ड्रेनेज ठीक करने का काम होगा और दस हज़ार एकड़ के लिए बंधियां बनायी जायेंगी। चार सौ प्राइवेट ट्यूब-वेल विभाग के जरिए से खास कर कोआपरेटिव इरिगेशन सोसाइटियों के लिए बनाये जायेंगे। बड़ी संख्या में मेसनरी कुएं गलाये जायेंगे। छः हज़ार रहट या परशियन व्हील लगाये जायेंगे। इस ग़रज़ से कि १९५४–५५ तक पूरे राज्य में 'ए' क्लास के बीज की वृद्धि हो जाय एक ड्राइव किया जायगा। धान की काश्त करने वालों को बीस हज़ार टन एमोनियम सल्फ़ेट तक़सीम किया जायेगा। फ़सलों के मुक़ाबिले की योजना को और कारामद और दिलचस्प बनाया जायगा। खास योजना के जरिए से यू० पी० राजपूताना सरहद पर बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए एक जंगलात का बेल्ट क़ायम किया जायगा। पशु-पालन विभाग की तरफ़ से एक योजना चन्द जिलों में ऐसी जारी की जायगी जिसके जरिए से जानवरों को छूत से लगने वाली बीमारियों को खत्म करने का बन्दोबस्त हो जाय और एक दूसरी योजना द्वारा अल्मोड़ा, गढ़वाल और चकराता में ऊन की तरक्क़ी का काम होगा। एक बड़े पैमाने पर टैनिंग (tanning) वग़ैरह में ट्रेनिंग देने का भी इन्तजाम कराया जायगा। इस साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर फ़िशरीज को तरक्क़ी दी जायगी। विद्युत् विभाग में हरदुआगंज पावर स्टेशन में पावर बढ़ाने का काम, रामपुर पावर हाउस में पावर बढ़ाने का काम और शाहजहांपुर में डिज़िल पावर स्टेशन बनाने का काम जारी रहेगा। सारदा पावर स्टेशन में, जिसमें इकतालीस हज़ार चार सौ किलोवाट बिजली पैदा की जायगी, पथरी पावर स्टेशन, जिसमें बीस हज़ार किलोवाट बिजली पैदा की जायगी, सारदा और गंगा ट्रांसमिशन सिस्टमों में और तेजी से काम होगा। ईस्टर्न एरिया पावर प्राजेक्ट (२७,५०० किलोवाट), मैनपुरी (१०,००० किलोवाट) में एक नये पावर स्टेशन और पहाड़ी जिलों में जल-बिजली (hydel) के छोटे-छोटे प्रोजेक्टों पर निर्माण-कार्य शुरू किया जायगा। रिहंद बांध प्राजेक्ट पर जो काम हो रहा है, वह जारी रखा जायगा। कानपुर पावर हाउस की ताक़त बढ़ाने का प्राजेक्ट (१५,००० किलोवाट) पूरा हो जायगा और उस से काम होने लगेगा। जहां तक सनती योजनाओं का ताल्लुक़ है राबर्टसगंज, मिर्ज़ापुर में सीमेंट फ़ैक्टरी बनाने का काम क़रीब क़रीब पूरा हो जायगा। यह आशा की जाती है कि इस फ़ैक्टरी में, जिसमें हर दिन ७०० टन सीमेंट तैयार होने की उम्मीद की जाती है, १९५४ के बीच तक सीमेंट बनने लगेगी। प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स फ़ैक्टरी में पानी के मीटर और अधिक तादाद में (पानी के ९,००० मीटर हर साल) बन कर तैयार होंगे और इसमें लगभग ५०० खुर्दबीन भी बनाये जायेंगे। रेशम और रेशम के कीड़े पालने के उद्योग-धंधों की तरक्क़ी के लिए लम्बे अर्से की एक नयी योजना शुरू की जायगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (Uttar Pradesh small scale and Cottage Industries Board) स्थापित किया है। इसके चेयरमैन मुख्य मन्त्री हैं और इसका कम छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले और घरेलू उद्योग-धन्धों से ताल्लुक़ रखने वाले मामलों पर सरकार को राय देना है। हैण्डलूम उद्योग की खास समस्याओं पर राय देने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया गया है। इन बोर्डों की रहनुमाई में हर ऐसी कोशिश की जायगी जिससे राज्य में घरेलू उद्योग-धंधे

जल्द स्थापित हो सकें। अब मैं यातायात में तरक्की करने की योजनाओं का जिक्र करूंगा। इस बात की आशा की जाती है कि अगले वर्ष में ३०० मील लम्बी नई सड़कों पर आमदरफ्त होने लगेगी। बहुत से पुलों पर होने वाला निर्माण कार्य पूरा हो जायगा। २५० मील लम्बी सड़क आधुनिक ढंग पर बनाई जायगी। शक्कर के कारखानों के हल्कों में कुल जितने मील लम्बे सीमेंट कंकड़ के रास्ते बने हैं उसमें काफी इजाफ़ा हो जायगा। गवर्नमेंट रोडवेज आर्गनाइजेशन की करीब २०० और गाड़ियां चलने लगेंगी। कानपुर और लखनऊ में मजदूरों के लिये मकान बनवाने की योजना पर, जिस पर ७५ लाख रु० खर्च किया जा रहा है, होने वाला काम पूरा हो जायगा। बेघर-बार लोगों के लिये लगभग ७०० क्वार्टर और ३३० दूकानें बनवाई जायंगी। जहां तक सामाजिक सेवाओं का ताल्लुक है शिक्षा पर होने वाला खर्च ४३ लाख रु० और बढ़ जायगा। यूनिवर्सिटियों को और अनुदान (grant) देने के लिये बजट में ३ लाख रु० की रक़म रखी गई है। गैर-सरकारी आर्ट्स कालेजों (Arts Colleges) और सेकंडरी स्कूलों को दिये जाने वाले अनुदानों की रकम में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य संबंधी अनुदानों के अधीन होने वाले खर्च में लगभग ४५ लाख रु० का इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन के प्रोग्राम के अधीन आगरा में एक टी० बी० क्लीनिक खोला जायगा। गेठिया (५० रोगी) और जहांगीराबाद (२५० रोगी) में नये टी० बी० सैनेटोरियम बनाये जायंगे। दस नये एलोपैथिक और पंद्रह नये आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय खोले जायेंगे। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को उसके आयुर्वेदिक कालेज के लिये कुल मिला कर १,२५,००० रु० के और अनुदान दिये जायेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी को उसके अस्पताल और डेंटल स्कूल की इमारतों के लिये कुल मिला कर १,६२,००० रु० के और अनुदान दिये जायंगे। डब्लू० एच० ओ० (W. H. O.) और यू० एन० आई० सी० ई० एफ़० (U. N. I. C. E. F.) की जेरे परस्ती में जच्चा और बच्चा की देखभाल करने की एक नई योजना बजट वर्ष में चालू की जायगी। इस पर लगभग ३० लाख रु० खर्च होगा। इस योजना का मकसद यह है कि अगले तीन साल में ऐसे २०० जच्चा-बच्चा हितकारी केंद्र खोले जायं जिनमें हर तरह का सामान मुहैया हो। मलेरिया-निरोधक दो बड़ी योजनायें जो डब्ल्० एच० ओ० (W. H. O.) और एफ० ए० ओ० (F. A. O.) से मशविरा लेकर बनाई गई हैं। तराई क्षेत्रों में और चौबीस चुने हुये उन जिलों में लागू की जायंगी जहां लोग मलेरिया से अधिकतर बीमार पड़ा करते हैं। जहां तक मजदूरों की भलाई का ताल्लुक है, मजदूरों के लिये मकान बनवाने की मौजूदा योजनाओं के अधीन मकान बनवाने का जो काम हो रहा है वह जारी रखा जायगा और यदि केंद्र से माली सहायता मिली तो इसी तरह की और योजनायें चालू की जायंगी। बजट वर्ष में हरिजन सहायक विभाग का खर्चा लगभग ५५ लाख रु० बढ़ जायगा। दूसरी तजवीज जिसका मैं यहां पर हवाला देना चाहता हूं जोतों (holdings) की चकबन्दी से ताल्लुक रखती है, हालांकि माली नुक्ते नजर से यह अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुई है। यदि गिज़ा की पैदावार बढ़ाना है तो एक बहुत ही जरूरी सुधार यह करना है कि ऐसे जोतों की चकबन्दी की जाय जिनसे कोई फायदा न हो। इस तजवीज़ को लागू करने में अब तक बहुत सी अड़चनें सामने आती थीं। जमींदारी खत्म करने से इनमें से बहुत सी अड़चनें दूर हो गई हैं। अगले माली साल में इस तजवीज को लागू करने के लिये कदम उठाये जायंगे। ऐसी सूरत में कि इस बजट में यह चीजें हों और बावजूद इस बात के कि उसमें कुछ कमियां भी बताई जा सकती हैं उसको यकीनन एक वेलफेयर स्टेट का बजट कहा जाना चाहिये।

५–वेलफेयर स्टेट का चर्चा मैंने इस जगह इसलिये किया कि सरकार यह चाहती है कि सिर्फ पढ़े-लिखे और शहरों के रहने वालों ही तक बजट से दिलचस्पी महदूद न हो बल्कि शहरी और देहाती यानी आम जनता उसको अपना बजट समझ सके और उसकी बुराई-भलाई पर नजर रखते हुये फायदा पहुंचाने वाली आलोचना कर सके, बजट की चर्चा गांव–गांव हो, हर एक को उससे दिलचस्पी हो और लोग जानें कि हमारी और हमारी

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

सरकार की माली हालत क्या है, देश को क्या जरूरत है और इन जरूरतों को पूरा करने के साधनों के बारे में क्या होना चाहिये। जनता को इस किस्म की दिलचस्पी जभी पैदा हो सकती है जबकि बजट एक वेलफेयर स्टेट का बजट हो और आम आदमियों की जरूरत पूरा करने की तरफ उसका कदम बढ़ रहा हो।

६—गवर्नमेंट ने इस राज्य के वेलफेयर के लिये जो काम किये मैं उनका कुछ जिक्र ऊपर कर चुका हूं। लेकिन यहां कुछ और कामों की तफसील इसलिये बयान करना जरूरी समझता हूं कि माननीय सदस्य हुकूमत के सार्वजनिक कामों का एक पूरा खाका देख लें।

७—गुजरे चंद सालों में सरकारी विभागों के काम के फलस्वरूप औसतन हर साल २० लाख मन से लेकर ३० लाख मन तक गन्ने का तरक्कीयाफ्ता बीज, २ लाख मन से ४ लाख मन तक खली की टिकियां, खाद और खाद देने वाले औजार और ५० लाख मन मिला हुआ खाद सारे प्रदेश में तकसीम किया जाता है। कृषि विद्या के सिलसिले में कृषि विद्यालय को काफी तरक्की दी गई है। कृषि विद्या के लिये एक नया कालेज खोला गया है और तालिबइल्मों को उनके काम और मेहनत का मुआवजा देने का एक नया तरीका ईजाद किया गया है। जराअत और फने बागबानी के सिलसिले में अच्छा काम किया गया है और जमीन की छानबीन और परख के सिलसिले में भी खूब काम हुआ है। पौदों की हिफाजत के तरीके बताने का काम भी हो रहा है जिससे कृषि में दिलचस्पी लेने वालों को काफी फायदा पहुंचा है। इस सदन को यह सुनकर खुशी होगी कि विकास की एक खास स्कीम के मातहत तकरीबन १ लाख एकड़ जमीन जूट के नीचे है और इस पदार्थ के सिलसिले में हमारी स्टेट अब किसी की मुहताज नहीं। जानवरों की देख-रेख के सिलसिले में गवर्नमेंट का सबसे पहला मक़सद यह है कि जानवरों में छूत की बीमारियां फैलने को जल्द अज जल्द खत्म कर दिया जाय और दूसरा यह कि हर क़िस्म के जानवरों की अच्छी नस्लें तैयार की जायं ताकि खेती-बाड़ी और दीगर जरूरियात के लिये अच्छे जानवर मुहय्या हो सकें। फिशरीज में भी गवर्नमेंट काफी दिलचस्पी ले रही है ताकि इस प्रदेश के लोगों को एक सस्ती और उम्दा गिजा आसानी से मिल सके। गाड़ियों में जोतने वाले बैल और भैंसों की नस्लें तैयार करने के लिये और दूसरे जानवरों के अच्छे और उम्दा गल्ले तैयार करने के लिये पूरे प्रदेश में ११ मेकेनाइज्ड फार्म (mechanised farm) बनाये गये हैं जो १९ हजार एकड़ जमीन पर फैले हुये हैं। इसमें से बारह हजार एकड़ जमीन पर काश्त होती है ताकि यह फार्म अपनी किफायत आप कर सके। पिछले साल इन फार्मों से ३०५ जानवर निकले। इसके अलावा इन फार्मों के मुर्गीखानों में पोल्ट्री की तरक्की के लिये २ हजार से ज्यादा परिन्द निकाले गये। ताकि थोड़े नर-जानवरों से काम लिया जा सके इसलिये मसनुई तरीक़े से बच्चे पैदा कराने के तीस मरकज राज्य भर में खोले गये हैं। जानवरों को छूत के मर्जों से बचाने के लिये बड़े पैमानों पर टीके लगाने का काम किया गया है। इस साल ३८ लाख से ज्यादा जानवरों को टीका लगाया गया है। जानवरों की वैक्सीन प्रदेश में और ज्यादा ईजाद और ज्यादा तैयार की जाने लगी है। जानवरों के तकरीबन २२ शफाखाने और स्थापित किये गये हैं। मथुरा में एक कालेज सिर्फ इस गरज से खोला गया है कि उसमें जानवरों की देखरेख और उनके इलाज की तालीम दी जाये। फिशरी में तरक्की के लिये एक अलग संगठन किया गया है ताकि प्रदेश में पानी के जो टुकड़े खाली पड़े हैं उनको मछलियों से आबाद कर दिया जाय। ५८५ तालाब ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली मछलियों से आबाद किये गये हैं। कानपुर में एक ऐसा ब्वायलर स्थापित किया गया है जो एक घंटे में १,५०,००० पौंड पानी को भाप में तब्दील करता है जिसके जरिये से १५,००० किलोवाट बिजली तैयार की जाती है। इन्डस्ट्री के सिलसिले में सब से महत्वपूर्ण काम जो हो रहा है वह रौबर्टसगंज, जिला मिर्जापुर, में ७०० टन योमिया सीमेन्ट तैयार करने वाली सीमेन्ट फैक्ट्री का काम है। फैक्टरी की दफ्तर

वाली इमारतें बन कर तैयार हो गई हैं । फैक्टरी के लिये ६,६०० टन की जिन मशीनों आदि के लिए आर्डर दिये गये थे उनमें से ५,००० टन की मशीनें आदि आ गई हैं और लगाई जा रही हैं। लखनऊ के गवर्नमेंट प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी (Government Precision Instuments Factory) में पानी के करीब २,००० मीटर अब हर साल बनाये जा रहे हैं। खुर्दबीन (microscope) का बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। घरेलू उद्योग-धंधों की तरक्की के लिये १३४ ऐसे केन्द्र खोले गये हैं जिनमें ट्रेनिंग भी दी जाती है और सामान भी बना कर तैयार किया जाता है, ताकि सामान तैयार करने के उन्नतिशील ढंगों में ट्रेनिंग दी जा सके और डिज़ाइन तथा फिनिश में तरक्की की जा सके। मऊ (आज़मगढ़) में सामान फिनिश करने और रंगने का कारखाना स्थापित किया गया है। खादी बनाने के हुनर में २०,००० बुननेवालों को ट्रेनिंग दी गई है। लखनऊ में फल हिफाजत से रखने और उन्हें डब्बों में बन्द करने का कारखाना स्थापित किया गया है। घरेलू उद्योग-धंधों द्वारा बनाये गये सामान के स्तर या उनकी किस्म (quality) पर नियंत्रण रखने के लिये एक योजना चलाई गई है। लखनऊ और इलाहाबाद में दो व्यावसायिक (occupational) स्कूल, गाज़ीपुर में एक टेक्निकल स्कूल, हमीरपुर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल और अल्मोड़ा, श्रीनगर, टेहरी, मेरठ और देहरादून में हर जगह एक-एक पोलीटेक्निक स्कूल खोले गये हैं। इनके अलावा हैंडलूम कपड़ा बनाने के लिए चार केन्द्र और ऊनी कपड़ा बनाने के लिये तीन केन्द्र खोले गये हैं। जहां तक भवन और सड़क विभाग का ताल्लुक़ है माननीय मेम्बर यह देखेंगे कि आधुनिक ढंग पर सड़कें बनाने का तरीक़ा धीरे-धीरे सारे राज्य में अपनाया जा रहा है। लगभग २,१५० मील स्थानीय पक्की सड़कें फिर से बनाई जा चुकी हैं और लगभग २,२०० मील नई सड़कें बनकर तैयार हो रही हैं ५,००० मील से ज्यादा कच्ची सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इनके अलावा सीमेंट और कंकड़ से ५० मील लम्बे पक्के रास्ते बन चुके हैं। बेघर-बार वालों के लिये १२८ दो-कमरे वाले और ६५२ एक-कमरा वाले क्वार्टर तथा ४२ दूकानें बन चुकी हैं। लखनऊ और कानपुर में मज़दूरों के लिये मकान बनवाने की एक महत्वपूर्ण योजना, जिस पर लगभग ७५ लाख रु० ख़र्च होने की सम्भावना है, शुरू कर दी गई है। ख़र्च में सब से ज्यादा इजाफ़ा शिक्षा पर हुआ है। १९,००० से ज्यादा नये प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं। ८६ म्यूनिसिपैलिटियों में लड़कों के लिये अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा (compulsory primary education) चालू कर दी गई है। ३१ नये कालेज खोले जा चुके हैं । इसी तरह जूनियर हाई स्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और टेक्निकल स्कूलों की तादाद भी बढ़ गई है। रुड़की यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल शिक्षा दी जाती है उसका स्टैण्डर्ड ऊंचा कर दिया गया है। शिक्षा पाने वाले बच्चों की तादाद में १२ लाख से ज्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। जहां तक चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य का ताल्लुक है एलोपैथिक औषधालयों की संख्या ४९ से बढ़कर २८६ और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों की संख्या २२६ से बढ़ कर ५२१ हो गई है। डफरिन और जिला अस्पतालों का, जिनका प्रबन्ध पहिले स्थानीय निकायों (local bodies) द्वारा होता था और अधिकतर जिनमें ज़रूरी सामान न था, प्रान्तीयकरण (provincialization) हो गया है और उनमें ज़रूरी सामान, जैसे एक्स-रे यन्त्र, रोगी लाने की गाड़ियां आदि, मुहैया कर दिया गया है। डाक्टरी शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें दी गई हैं और मेडिकल कालेजों में भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थियों की तादाद १२५ से बढ़ाकर २०० कर दी गई हैं। बहुत से पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स चालू किये गये हैं। नये टी० बी० सैनोटोरियम खोले गये हैं और तपेदिक से बचने के लिये बी० सी० जी० के टीके बड़े-बड़े शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर लगाये गये हैं। सब बड़े-बड़े मेलों में महामारी के टीकों का लगवाया जाना ज़रूरी कर दिया गया था और इस तरह महामारी के रोगों पर कामयाबी से काबू पा लिया गया था। मलेरिया-निरोधक कार्यवाहियां बड़े पैमाने पर की गई हैं। दाइयों की ट्रेनिंग देने के लिये २३० केन्द्र स्थापित किये गये हैं। कानपुर में स्थानीय

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मजदूरों के फायदे के लिये इम्लाईज़ स्टेट इंश्योरेन्स स्कीम चालू की गई है। आमतौर पर मजदूरों के लिये बहुत सी कल्याणकारी योजनायें राज्य भर में चालू की गई हैं। मजदूरों और मिल मालिकों के बीच झगड़ों का मित्र-भाव से समझौता कराने के लिये समझौता बोर्ड (Conciliation Boards) और स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल स्थापित किये गये हैं। । बहुत से उद्योग-धंधों में कम से कम मजदूरी नियत कर दी गई है। कपड़े और चमड़े के उद्योगों में छटनी किये गये और आकस्मिक तौर पर काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्री होने और उन्हें काम पर लगाने के लिये एक पूल (pool) योजना कानपुर में चालू की गई है। राज्य के मुख्तलिफ़ शहरों में लगभग ४९ श्रमहितकारी केन्द्र (Labour Welfare Centres) स्थापित किये गये हैं। कानपुर में मजदूरों के लिए एक खास टी० बी० क्लीनिक खोला गया है। शक्कर उद्योग के मजदूरों के लिये मकान बनवाने की योजना (Sugar Industry Housing Scheme) के अधीन शक्कर के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये २४२ मकान बनाये गये हैं तथा और मकान बन रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि पहिले कहा जा चुका है राज्य-सहायता के आधार पर मकान बनवाने की योजना (Subsidized Labour Housing Scheme) के अधीन जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, २,७७७ छोटे-छोटे मकान बनवाने का काम लखनऊ और कानपुर में शुरू हो गया है।

८—पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश पर एक के बाद एक कृषि सम्बन्धी मुसीबतें आती रही हैं। इससे पूर्वी ज़िलों के कुछ हिस्सों में खाने-पीने के सामान की बेहद कमी हो गई थी। सरकार इन क्षेत्रों के संकट को दूर करने का हर प्रकार से बराबर प्रयत्न करती रही है। इस दशा में सहायता-कार्य के मद में १३५९ फसली में पचास लाख पचासी हजार सात सौ बयासी रुपये की लगान और पन्द्रह लाख अठहत्तर हजार एक सौ छियालिस रुपये की मालगुजारी में छूट दी गई। विभिन्न कामों के लिये ९७,१३,१०० रु० तकावी के रूप में बांटा गया जिसमें से १९,३०,००० रु० संकट-कालीन तकावी के रूप में पेशगी दिया गया था। ५५,१२,००० रु० की रकम टेस्ट और रिलीफ के काम में लगाई गई ताकि संकटों के कारण जिन ग़रीब छोटे किसानों या भूमि-रहित मजदूरों या अन्य बेबस देहाती भाइयों के लिये अपना पेट भरने का साधन नहीं रह गया था, उनको कुछ काम दिया जा सके। ९,६९,००० रु० देहात के बूढ़े, अपाहिज, निराधार और मासूम बच्चों की सहायता के लिये मंजूर हुआ जिनको वास्तव में साधनहीन समझा गया। ऐसे जरूरत-मंद लोगों के लिये मुफ्त कपड़ों का इन्तजाम किया गया और इस प्रकार ९२ गांठ कपड़ा पीड़ित क्षेत्रों में बांटा गया। दुर्बलता में सहायता के लिये दूध का पाउडर तथा विटेमिन की गोलियां बांटी गईं। इस प्रकार अनेक प्रकार की सहायता दी गई।

९—पिछले चन्द मिनटों में मैंने जो कुछ कहा है उसमें मैंने सिर्फ़ उन फ़ायदों का ज़िक्र किया है जो सरकार के प्रयत्नों द्वारा जनता को पहुंचे हैं और सिर्फ़ इन्हीं के ज़िक्र में काफ़ी वक्त लग गया है। मैंने ब्योरे नहीं दिये हैं और न यह दिखाने का प्रयत्न ही किया है कि इनसे जनता को कितना फ़ायदा पहुंचा है, हालांकि यह समझने के लिए कि जो काम हुआ है उसकी कितनी अहमियत है यह जरूरी है कि और अधिक गहराई में घुसा जाय। वास्तव में मैंने इसमें मुख्तलिफ़ विभागों, जैसे वन विभाग, सहकारी विभाग, अमन और शान्ति, न्याय, बेघर-बार लोगों को सहायता देने और उन्हें फिर से बसाने आदि से सम्बन्ध रखने वाले विभागों के कार्यों का ज़िक्र नहीं किया है, हालांकि इन विभागों ने भी आर्थिक और सामाजिक महत्व रखने वाली बड़ी-बड़ी योजनायें चलायी हैं। और न मैंने उन कार्यवाहियों का ज़िक्र किया है जो सरकार ने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने, कमी वाले क्षेत्रों में कष्ट दूर करने, कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की हालतों में सुधार करने, सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी और कुशलता (efficiency) बढ़ाने आदि के लिए की हैं। इस डर से कि इनके ज़िक्र में आपका बहुत

समय बर्बाद होगा मैं इन मदों के बारे में कुछ न कहूंगा। फिर भी मैं यह समझता हूं कि जो कुछ भी मैं कह सका हूं, वह यह बतलाने के लिए काफ़ी होगा कि बहुत सा ठोस काम हुआ है।

१०–अब यह मौजूं मालूम होता है कि मैं सदन के सामने बजट की वे संख्याएं रखूं जिनसे प्रदेश की १९५१–५२ की मालियाती पोज़ीशन स्पष्ट होती है। इनमें चालू वर्ष के द्वारा जांचे हुए तख़मीने और अगले वर्ष के बजट के तख़मीने हैं।

११–नीचे की संख्याओं से १९५१–५२ की मालियाती पोज़ीशन का पता चलता है :

	लाख रुपयों में	
	मूल बजट (Orignal budget)	वास्तविक आंकड़े (Actuals)
आरम्भिक शेष (Opening Balance)	९१,	७,१४,
(१) संचित निधि (Consolidated Fund)		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)—		
(१) प्राप्तियां (Receipts)	६१,२६,	५५,५६,
(२) व्यय (Charges)	६१,५१,	५५,५०,
	—२५,	+६,
(ख) पूंजी व्यय (Capital Expenditure)	१६,७९,	१०,५५,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net Receipts from Public Loans)	+४,००,	+१,४३,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other Debts and Deposit Heads (Net)]	+११,३९,	+२,०४,
(२) आकस्मिकता व्यय निधि (Contingency Fund)	...	...
(३) सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public Account (Net)]	+१,६१,	+१०
इस वर्ष में हुए सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all transactions in the year)	—४,	—६,९२,
अन्तिम शेष (Closing Balance)	८७,	२२,

१२–बजट यह समझकर बनाया गया था कि गुज़रे हुए साल के दौरान में ज़मींदारी का खात्मा हो जायगा, हालांकि ऐसा बाद वाले साल में हो सका। इसी सबब से राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय (Revenue Receipts and Revenue Expenditure) में गिराव हुआ। नहरें और सड़कें बनाने में चूंकि रफ्तार तेज़ न रह सकी इस वजह से साल के अन्त में २५ लाख रु० की कमी के बजाय थोड़ी सी बचत रही।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

१३--नीचे लिखे हुए अंक चालू साल के दोहराये हुए तखमीनों को दिखाते हैं :

	लाख रुपयों में	
	मूल बजट (Original Budget)	दोहराये तखमीने (Revised)
आरम्भिक शेष (Opening Balance)	२२,	२२,
(१) संचित निधि (Consolidated Fund)--		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)--		
(१) प्राप्तियां (Receipts)	६०,९९,	६६,४१,
(२) व्यय (Charges)	६५,२३,	६६,४१,
	-४,२४,	....
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure)	२०,७४,	१५,६१,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans)	+११,००,	+८,११,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debts and Deposit heads (Net)]	+३,८८,	+२,३७,
(२) आकस्मिकता व्यय निधि (Contingency fund)	...	...
(३) सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public Account (Net)]	+११,८०,	+६,८६,
इस वर्ष में हुए सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all transactions in the year)	+१,७०,	+१,७३,
अन्तिम शेष (Closing balance)	+१,९२,	+१,९५,

१४—इब्तिदाई तख़मीनों में ४.२४ रु० की कमी दिखायी गयी थी। दोहराये गये तख़मीनों से बाहिर होता है कि जंगलात की प्राप्तियां, एक्साइज़ की प्राप्तियां और "दूसरे कर और महसूल (Taxes and Duties)", "असाधारण प्राप्तियां" उम्मीद के ख़िलाफ़ १·६९ करोड़ रु० कम हो जाने की सम्भावना है। इस साल जो पंचायतों के चुनाव होने वाले थे उनके मुल्तवी हो जाने की वजह से ०·७१ करोड़ रु० की और कमी हुई है। प्राप्तियों के गिराव को अगर दूसरी तब्दीलियों के साथ जो प्राप्तियों और ख़र्चों के तख़मीनों में जिनके वाक़े होने का इमकान है देखा जाय तो आमदनी और ख़र्चे (expenditure) में ६·४६ करोड़ रु० के अन्तर की सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार के एक्साइज़ रेवेन्यू में जो हिस्सा हमारे प्रदेश को मिला है, उसके बाद यह रक़म ३.२५ करोड़ रु० रह जायगी। ३·२५ करोड़ रु० की यह कमी राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से इतनी रक़म तबादिला करके पूरी कर दी जायगी।

१५—बजट के तख़मीने (Budget estimates) नीचे दिये गय हैं:

	लाख रुपयों में
आरम्भिक शेष (Opening balance)	१,९५,
(१) संचित निधि (ConsolidatedFund)—	
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue heads)—	
(१) प्राप्तियां (Receipts)	७४,३८,
(२) व्यय (Charges)	७८,८०,
	–४,४२,
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure)	७,०९,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from Public Loans)	+३,००,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debts and Deposit heads (Net)]	+६,२६,
(२) आकस्मिकता व्यय निधि (Contingency Fund)	...
(३) सार्वजनिक लेखा शुद्ध (Public Account net)	+१,६६,
इस वर्ष में हुए सभी लेन देन का शुद्ध फल (Net result of all transactions in the year)	–५९,
अन्तिम शेष (Closing balance)	१,३६,

१६—चालू मालियाती साल का १/४ गुज़रने के बाद ज़मींदारी का ख़ात्मा कर दिया गया। इस कारण से सिर्फ़ एक फ़स्ल से सम्बन्धित मज़ीद मालगुज़ारी बक़ाया रह गयी है। अगले साल दोनों फ़स्लों की मज़ीद मालगुज़ारी वसूल की जायगी। ४·७९ करोड़ रु० की बढ़ती इस साल के दोहराये हुए तख़मीनों में इसी वजह से है। सिंचाई की प्राप्तियां ३·१८ करोड़ रु० ज़्यादा होंगी। "बिजली के कर," "बिक्री कर की प्राप्तियां" और "गन्ना कर की प्राप्तियां" में ०·८०, करोड़ रु०, ०·५४ करोड़ रु० और ०·२० करोड़ रु० की बढ़ती होगी। पंचायत चुनाव की प्राप्तियां ०·७० करोड़ रु० ज़्यादा होगी। मोटर गाड़ियों के ऐक्टों और ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की प्राप्तियां ०.३२ करोड़ रु० और ०.५५ करोड़ रु० ज़्यादा होगी। इन बातों से प्राप्तियों

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

क अांकड़े ६३·१६ करोड़ रु० [दोहराया हुआ तख़मीना जिसमें राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से वी गई रक़म शामिल नहीं है] से बढ़कर ७४.३८ करोड़ रु० हो गये हैं। मालगुजारी में जो इज़ाफ़ा हुआ है, उसमें से उन्नति के कामों के लिए कुछ न मिल सकेगा क्योंकि यह सब का सब ज़मींदारी विनाश का मुआवजा और रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट बांड्स (Rehabilitationr Gant Bonds) के मुताल्लिक़ सूद और अदायगी में और उन वक़्फ़ों (Works) और शिक्षा सम्बन्धी इदारों को और वाजिबात देने में जिनकी ज़मींदारी ज़ब्त हुई है, मालगुजारी वसूल करने के बढ़े हुए ख़र्च और इसी तरह के ख़र्चों के पूरा करने में ख़त्म हो जायगी। कुल बढ़ी हुई प्राप्तियां सिंचाई और हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स (Hydro Electric Works) पर पूंजी से किये जाने वाले उन्नति के ख़र्चों को पूरा करने के लिए ख़ास विकास निधि (Special Development Fund) में जमा कर दी जायेंगी। दूसरी तरफ़ विकास विभागों में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) चालू मालियाती साल के दोहराए गये तख़मीनों से २·२२ करोड़ रु० ज्यादा होंगे। इसका ज़िक्र पहले भी हो चुका है कि इसमें ३·२५ करोड़ रु० की कमी की सम्भावना है [जिसकी पूर्ति राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से की जायगी] । इन बातों का और प्राप्तियों और ख़र्चों में दूसरी तब्दीलियों का नतीजा यह निकलेगा कि आइन्दा साल ४·४२ करोड़ रुपये की कमी की सम्भावना है।

१७—यह याद रखना चाहिए कि अगर हम चालू साल की प्राप्तियों और ख़र्चों का मुक़ाबिला आइन्दा साल से करें तो बिलतरतीब ६०·९९ करोड़ रु० की "प्राप्तियां", ६५·२४ करोड़ रु० का "खर्चा" और ७४·३८ करोड़ रु० की "प्राप्तियां" और ७८·८० करोड़ रुपया का "खर्चा" नज़र आता है। इस तरह भारत के तमाम राज्यों में हमारे उत्तर प्रदेश की प्राप्तियां और खर्चा सब से ज्यादा है।

१८—यह भी मालूम होगा कि प्राप्तियों और ख़र्चों के आंकड़े दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (other debt and deposit head) के तहेत यकलख्त ८० करोड़ रु० तक चले गये हैं। यह बात महज इस वजह से है कि पुराने ज़मींदारों को ख़ात्मए ज़मींदारी का मुआवजा और (Rehabilitation Grant Bonds) दिये जायेंगे। चुनांचे टेक्निकल नुक्तएनज़र या दृष्टिकोण से यह कहना बेजा होगा कि स्टेट इसी क़दर ज़ेरबार हो जायगी जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ज़मींदारी के ख़ात्मे के बाइस जो ज़ेरबारी हो गयी उसको मालगुज़ारी के शुद्ध बढ़ोत्तरी से पूरा कर लिया जाय। इसलिए यह बात साफ़ है कि इस क़र्ज़े को निबटाने में स्टेट को कोई दिक़्क़त नहीं पेश आयेगी।

१९—इस बजट के सालमें वह क़र्ज़ा भी जो मामूलन सरकार अपने बढ़े हुए ख़र्च को पूरा करने के लिए लिया करती है बढ़ा हुआ है। उन्नति और विकास के बढ़ते हुए कामों के साथ साथ यह ज़ेरबारी लाज़िमी है लेकिन इस सदन के सदस्य इस बोझ से परेशान न हों। अगर सरकार की तवज्जह इस तरह है कि विकास के काम तेज़ी से हों तो सरकार इस हक़ीक़त से भी बेख़बर नहीं है कि प्रदेश की मालियाती पोज़ीशन मज़बूत रहे। अगरचे क़र्ज़ों की अदायगी के सिलसिले में सरकार कोई ज़ख़ीरए अदायगी (sinking funds) खोलने की पाबन्द न होगी, लेकिन फिर भी सरकार ज़ख़ीरए अदायगी (sinking funds) खोलने के लिए और उनमें इतनी रक़म डालने के लिए तैयार है कि मुक़र्ररा मियाद में क़र्ज़े अदा हो जायं। मैं यह भी साफ़ कर देना चाहता हूं कि ख़ात्मये जमींदारी बांडस् (Zamindari Abolition Bonds) के मुनाफ़े को छोड़ कर जो बढ़ाई हुई मालगुज़ारी से, जो ख़ात्मए ज़मींदारी के बाद इज़ाफ़ा हुए हैं, अदा किये जायेंगे और तमाम सूद जो राज्य के लिए हुए क़र्ज़ों पर होगा उन प्राजेक्ट्स के मुनाफ़ों से अदा किया जायगा जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए सरकार ने क़ायम किये हैं या करने वाली है। इस सिलसिले में इस से बेहतर शक्ल मुमकिन न थी। इससे सरकार को बहुत सन्तोष है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस पर अपने पूरे सन्तोष का इज़हार करेगा।

२०––मैं यहां पर पंचवर्षीय योजना की कुछ चर्चा करना चाहूंगा। भारत सरकार ने भारतबासियों के रहन-सहन को ऊंचा करने और आमदनी को बढ़ाने के लिये एक प्लानिंग कमीशन बिठलाया है और उसके सिपुर्द यह काम किया है कि वह एक ऐसा प्लान बनाये जिसमें भारत के सभी राज्यों की योजनाएं शामिल हों, जिनका मकसद विकास उन्नति और आर्थिक स्थिति का बढ़ाना हो और उसके जरिये पैदाबार बढ़ाई जाय ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ाने के लिये यह बात सामने रखी गई है कि बीस बाइस साल में फीक्स आमदनी दुगनी हो जाय और नेशनल इनकम जो १९५१–५२ में नौ हजार करोड़ रुपया थी सन् १९५६ में दस हजार करोड़ रुपया हो जाय यानी उसमें एक हजार करोड़ रु० या ग्यारह फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाय और जो बढ़ोत्तरी हो वह महज चन्द आदमियों के पास इकट्ठी न हो बल्कि उसका वितरण या तकसीम ऐसी हो कि आमदनियों में आज जो कमी और ज्यादती दिखाई देती है वह न रहे।

२१––इस योजना में कृषि, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, जंगलात, कोआपरेटिव, फिशरीज़, इंडस्ट्री, ट्रांस्पोर्ट, पी० डब्ल्यू० डी०, सोशल सर्विस, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ या स्वास्थ्य इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिये मकानात, मजदूरों की भलाई और पिछड़े हुए लोगों के उभार से संबंधित उत्तर प्रदेश की योजनाएं शामिल हैं। प्लान का सब से बड़ा हिस्सा (जिसकी लागत ४१·७ करोड़ रु० है) वह है जिसमें खेती, पशु पालन और सिंचाई की तरक्की की योजनायें शामिल हैं। सिंचाई की योजनाओं में कई बांध, जलाशय (reser voirs), कंटूर बंधियां, हजारों ट्यूबवेल, हजारों मील लम्बी सिंचाई की नालियां आदि बनाने की तजवीज है जिनसे पैंतीस लाख से चालीस लाख एकड़ ऐसी भूमि में सिंचाई की जा सकेगी जिसमें पहिले सिंचाई की सहूलियतें न थीं। प्लान की खेती सम्बन्धी स्कीमों में ऐसी योजनायें, जैसे जंगली क्षेत्रों को साफ करना, ऊसर जमीन खेती योग्य बनाना और पानी भरे रहने वाले भूमि के टुकड़ों से पानी निकालना, शामिल हैं ताकि बहुत सी ऐसी जमीन में जो बेकार पड़ी है खेती की जा सके। इन योजनाओं में सिंचाई सम्बन्धी छोटी योजनायें, जैसे पक्के कुएं गलाना या उन्हें फिर से खोदना, रंहटें या पम्प द्वारा पानी निकालने के यंत्र लगाना और राज-सहायता (Subsidy) के आधार पर विभाग की मदद से निजी ट्यूबवेल लगाना, शामिल हैं। इनके अलावा इस मद में अच्छे किस्म के बीज, खाद और खेती के औजार किसानों में बांटने, खेती के तरक्की किये हुये तरीकों के बतलाने, खेती और बागवानी सम्बन्धी खोज के काम को आगे बढ़ाने आदि की मुख्तलिफ दीगर योजनायें शामिल हैं। प्लान की पशु-पालन सम्बन्धी स्कीमें राज्य में खेती के काम में लाये जाने वाले हर तरह के पशुओं की जिनमें कुक्कुट-पालन शामिल है, नस्ल सुधारने, मछली से सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय में तरक्की करने, मवेशियों में छत की बीमारियों को रोकने, मवेशियों के वैक्सीन तैयार करने, डेरी फार्मिग और बाहर काम करने वालों को बड़ी तादाद में ट्रेनिंग देने से ताल्लुक रखती हैं। यदि सिंचाई, खेती और पशु-पालन सम्बन्धी स्कीमें नियत समय के अन्दर ही पूर्ण तौर पर चालू हो जायंगी तो गिजा के मामले में राज्य अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकेगा और शहरों और कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में गल्ला सप्लाई करने और उसे बांटने पर जो बहुत खर्चा सरकार आज कल बेकार कर रही है वह बच जायगा। मैं समझता हूं कि मेरे यह कहने में किसी को एतराज न होगा कि इस मक़सद को हासिल करने में मदद देने वाली स्कीमों को चालू करने में जो और अधिक रुपया खर्चा होगा उसे सरकार को मंजूर कर लेना चाहिये और किसी न किसी तरह से रुपया मुहैया करने के और जराय ढूंढे जाने चाहियें।

२२––प्लान का दूसरा अहम हिस्सा, जिस पर लागत लगभग १४.१ करोड़ रु० है बिजली और अधिक पैदा करने वाली योजनाओं से ताल्लुक रखता है। यह जाहिर है कि अगर राज्य के लोग खेती के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो, उन्हें समझती मामले में न सिर्फ देश के और हिस्सों के बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ कदम बढ़ाना होगा। आजकल

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जितनी बिजली मिल रही है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करना सनती तरक्की का पेश खीमा है। इसलिये प्लान में बहुत से नये बिजली घर स्थापित किये जाने, कुछ मौजूदा बिजली घरों की ताकत (capacity) बढ़ाने, बहुत लम्बी ट्रान्समिशन लाइनें बनाने आदि का बन्दोबस्त किया गया है । इसे भी न टाला जा सकने वाला खर्च समझना चाहिये और इसके लिये जरूरी जराय ढूंढ़े जाने चाहिये।

२३—इसी तरह यदि हमारा यह पक्का इरादा कि इस राज्य के लोगों का आर्थिक स्टैंडर्ड ऊंचा हो सिर्फ हवाई किले बनाना ही नहीं है तो, प्लान में ऐसे बड़े-बड़े सनअती प्रोजेक्टों पर, जैसे मिर्जापुर का सीमेंट फैक्टरी प्राजेक्ट जिस पर काम हो रहा है, २.८ करोड़ रु०, हमारी सड़कों और ट्रांस्पोर्ट की तरक्की पर ६.४ करोड़ रु० और घरेलू उद्योग-धंधों की उन्नति पर ३ करोड़ रु० का जो खर्च रखा गया है उससे बचा नहीं जा सकता।

२४—सामाजिक क्षेत्र में हमारा राज्य चिकित्सा, जन-स्वास्थ और शिक्षा के संबंध म जो सुविधायें अपने यहां के लोगों को अब तक दे सका है वे बहुत ही कम हैं। दूसरी बातों में उस वक्त तक तरक्की जल्द नहीं हो सकती जब तक कि तरक्की के साथ ही साथ शिक्षा संबंधी सहूलियतों, खास कर टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा की सहूलियतों का प्रबन्ध नहीं किया जाता। सनअती मामले में तरक्की होने के साथ मजदूरों की हितकारी योजनाओं की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे खुशहाली और तालीम की तरक्की होती जायगी वैसे ही वैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सहूलियतों की मांग जोर पकड़ती जायगी और एक जनतंत्रात्मक राज्य में इस मांग को मुनासिब हद तक पूरा करना ही पड़ेगा चाहे इसकी वजह से और बातों में तरक्की की रफ्तार धीमी ही क्यों न पड़ जाय। राज्य के पंचवर्षीय प्लान में इन सब बातों को वास्तविक तौर पर मान लिया गया है और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य श्रम हित (Labour Welfare) और दीगर सामाजिक सेवाओं से ताल्लुक रखने वाली योजनाओं के लिये २६.८ करोड़ रु० रखा गया है। मैं यह नहीं समझता कि इस सदन का कोई भी सदस्य यह सुझाव करेगा कि इस खर्चे में कमी की जाय या यह कि उसे पांच वर्ष के बाद के लिये आसानी से मुल्तवी किया जा सकता है।

२५—प्लान में दिया हुआ बाकी खर्चा जो ३ करोड़ रु० से कुछ ज्यादा है सहकारी संस्थाओं को बढ़ाने, वन संबंधी अर्थ-व्यवस्था फिर से ठीक करने (Rehabilitating Forest Economy) आदि की योजनाओं से ताल्लुक रखता है । यहां मुझे ब्योरे देने की जरूरत नहीं है लेकिन योजनाओं को जांचने से पता चलेगा कि वे कितनी अहम और जरूरी हैं।

२६—इस तरह यह साफ जाहिर है कि हालांकि प्लान के काम चालू करने के लिये जिस खर्चे की जरूरत है वह काफी ज्यादा है फिर भी देश के आवश्यक हितों को देखते हुये उसे किया ही जाना चाहिये और कोई ऐसी सरकार जो इस खर्चे को इसलिये टालना चाहे कि उसके जराय मुहैया करने में जो उसे नाखुशगवार कदम उठाने पड़ेंगे उनसे बचा जाय तो वह अपने फरायज अंजाम नहीं देती। जहां तक मौजूदा सरकार का ताल्लुक है मैं यह फौरन कह देना चाहता हूं कि उसने इस प्लान को अपनी पूरी ताकत से चालू करने का अहद कर लिया है। इसी तरह दूसरी राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय प्लान के उन भागों से पूरी तरह सहमत हैं जिनसे उनका ताल्लुक है। वास्तव में जहां तक पूरे प्लान का ताल्लुक है देश के सभी विचारवान लोगों ने उसका सरगरमी से स्वागत किया है और यदि मैं यह कहूं कि इस प्लान को चालू करने के लिये सरकारों को जनता से हुक्म मिल गया है तो यह गलत न होगा।

२७—इस तरह से यह बात तय है कि इस प्लान को चालू करने के लिये जो आवश्यक कदम उठाये जायंगे उनमें जनता की तरफ से मदद मिलेगी। इस समय बड़े पैमाने पर विकास का कोई प्रोग्राम चालू करने के लिये परिस्थितियां जितनी इस समय माफिक हैं

उतनी पहिले कभी न थीं। जैसा कि अभी कुछ देर पहिले मैं माननीय सदस्यों से कह रहा था कि अपने पिछले दौराने हुकूमत में इस राज्य सरकार ने विकास का जो प्रोग्राम चालू किया था उसमें हर कदम पर ऐसी आर्थिक और राजनैतिक अड़चनें आई जो देशव्यापी थीं और जिन पर हमारा कोई जोर न था। उनमें से बहुत सी अड़चनों पर काबू पा लिया गया है। बेघर-बार वालों को फिर से बसाने से ताल्लुक रखने वाली समस्यायें ज्यादातर हल हो गई हैं। अमन और शांति की हालत मजबूत हो गई है। सिक्के की बहुतायत (inflation) रोक दी गई है। सनती पैदावार बढ़ रही है और आमतौर पर कीमतें गिर रही हैं। पिछले पांच छः सालों में ज्यादा गल्ला पैदा करने के लिये जो मुख्तलिफ कदम उठाये गये थे वे अब एक एक करके अपने फायदे जनता को पहुंचा रहे हैं। देहातों में जमींदारी की जो हानिकर प्रथा थी उसे खत्म कर दिया गया है और किसानों को उस जमीन पर जिस पर वह मेहनत करता है मुस्तकिल हक दे दिया गया है। अब इस बात की सम्भावना है कि वह अपनी जमीन में और खेती के तरीकों को बेहतर बनाने में वाकई दिलचस्पी लेगा और इससे गल्ले की पैदावार बढ़ना लाजिमी है। इसके अलावा पंचायत राज की प्रथा चालू करके सरकार ने गांवों में जनतंत्र की भावना पैदा करने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। गांव वाले "अपनी मदद आप करो" की योजनाओं में जो हिस्सा ले रहे हैं उससे यह साफ जाहिर है कि वे अपनी तरक्की के लिये कितने फिक्रमन्द हैं। इन सब का नतीजा यह है कि राज्य गिज़ा के मामले में अपनी जरूरत आप पूरी करने की तरफ तेजी से जा रहा है। इस वजह से और इस बात से भी कि आम तौर पर कीमतें धीरे-धीरे गिर रहीं हैं सरकार अब इस हालत में है कि वह शहर के लोगों में राज्य सहायता के आधार पर गल्ला बांटना बन्द कर दे और उन भारी नुकसानों को रोक दे जो सरकार जनता को मुनासिब कीमत पर गल्ला सप्लाई करने के कारण उस समय उठा रही थी जब कि जिन्दगी की और जरूरियात की कीमतें गैर मुनासिब तौर पर बढ़ी हुई थीं। गिज़ा की इस बराबर सुधरती हुई हालत से भी अब यह मुमकिन हो सकेगा कि हम सप्लाई और राशन संबंधी अपनी माली जिम्मेदारियों को दिन ब दिन कम कर सकेंगे। आखीर में अहम बात यह है कि राज्य की मुस्तकिल आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। पिछले कई सालों से राज्य सरकार इस बात की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाती रही है कि हालांकि लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी पर असर डालने वाले सब क्षेत्रों में विकास करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है लेकिन राज्यों को दिये गये माली जराय उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये बिलकुल नाकाफी हैं। सीमित रूप में केन्द्रीय सरकार ने इस सवाल को फाइनेंस कमीशन के सुपुर्द किया था। मुझे यह कहने में खुशी है कि कमीशन की सिफारिशों की वजह से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने कुछ दिन हुये मान लिया है, तम्बाकू, दियासलाई और बनस्पति घी से होने वाली केन्द्रीय एक्साइज आमदनी में अब राज्य सरकारों का भी हिस्सा रखा गया है। राज्य की इन्कम-टैक्स की आमदनी के हिस्से में भी थोड़ी सी तरमीम कर दी गयी है। जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक़ है इसकी आमदनी पर जो इन्कम-टैक्स के हिस्से से हासिल होती है कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन एक्साइज की आमदनी से जो हिस्सा मिला है उस से राज्य की सालाना आमदनी में ढाई से साढ़े तीन करोड़ रुपये का इजाफ़ा होता है। बेशक यह एक खुशी की बात है, खास तौर से ऐसे वक्त में जब कि हमारी स्टेट माली संकट से गुजर रही है। यह बहुत ही क़ाबिले इत्मिनान बात है कि कमीशन ने ज्यादातर हमारी इस बात को मान लिया है कि मर्कज़ी आमदनी को मुख्तलिफ़ राज्यों में आबादी के हिसाब से तक़सीम किया जाना चाहिए। जाहिर है कि यह निहायत ही मुन्सिफ़ाना तरीकेकार है। इस लिए कि हुकूमतों के खर्चों का इनहिसार उस आबादी के तनासुब पर होता है जिसकी कि वह खिदमत करती हैं।

२८—चूंकि पैदावार बढ़ाना है और हमारे पूरे देश की पालनहार कृषि या खेतीबाड़ी रही है, इस खेती को प्रायरिटी (priority) और इसी वजह से सिंचाई और विद्युत को कमीशन ने सब से ऊंचा दर्जा दिया। यह कुदरती सी बात है और ऐसा होना ही चाहिये था। इस प्लान में इन स्कीमों में से जिन पर १९५१-५२ में काम हो रहा था चन्द

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

स्कीमें सम्मिलित या शामिल कर ली गईं। उन स्कीमों का चर्चा जिनका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है, जैसा कि मैंने पहले कहा, आगे किया जाने वाला है।

२९—जहां तक इस प्लान का ताल्लुक़ है, हमें उसकी अहमियत और अपने प्रदेश पर उसके असर को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिये कि उसके ज़रिये से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा विकास और उन्नति होगी। हमारे लिये प्लान का मामला "अभी या कभी नहीं" का मामला है। भारत में स्वतन्त्रता या आज़ादी आने के बाद देश के सुधार और विकास की जो जिम्मेदारी हम पर आई है उसको पूरा करने और हमारे दरम्यान जो आज दुःख मौजूद हैं उनको दूर करने के लिये यह योजना बनाई गई है। इसके द्वारा अगर हमको अपनी इक़्तसादी या आर्थिक स्थिति बढ़ानी है और हमारी जनता जिस स्थान पर आज है उसको उससे ऊंचा ले जाना है, अगर हमको यह देखना है कि ज़मींदारी की मंसूखी से उत्तर प्रदेश को क्या फ़ायदा पहुंचा है, तो हमें इस प्लान को बहुत अज़ीज़ और प्यारा समझ कर उसके मुताबिक काम करना चाहिये और जिनके हाथों में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना कारोबार दिया है उनको उस जनता का पूरा सहयोग मिलना चाहिये। कोई पूंजीवाला हो या दरम्यानी, ग़रीब हो या अमीर जो भी जो इमदाद कर सकता है, उसको वह हृदय से करनी चाहिए। विदेशी राज के दिनों में सरकार और जनता दो अलग चीजें होंगी मगर आज हरगिज़ ऐसा नहीं है। आज राज और प्रजा का अन्तर मिट चुका है। अब उनको एक समझना चाहिए और सभी को मिलजुल कर हिम्मत, हौसले, उत्साह और पूर्ण विश्वास और यकीन के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। समय बदलते रहेंगे, हुकूमतें आती और जाती रहेंगी, परन्तु यह सच्चाई और यह सिद्धान्त कि देश का उभार बग़ैर सभी के सहयोग और सरकार और जनता के तआउन या कोआपरेशन के बग़ैर नहीं हुआ करता, अमिट और हमेशा कायम रहने वाला है। यह कभी बदला और न आइन्दा बदलेगा। देश सब रहने वालों का है। इसका काम दलबन्दी और पार्टियों के राजनीतिक अन्तरों से बहुत ऊंचा है। वह किसी तरह का अन्तर किये बग़ैर हर एक से कुरबानी मांगता है और हम सब का कर्तव्य या फर्ज़ है कि अन्तरों या इख्तलाफों को भूलकर उसकी यानी देश की सच्ची सेवा करें और प्रेम के साथ एक दूसरे का हाथ बटायें।

३०—अब मैं दो चार बातें ऐसी अर्ज़ करना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बजट में पहली दफ़ा जगह पाई है। उनमें से एक बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो काम होने वाले हैं उनमें ऐसे भी हैं जो श्रमदान द्वारा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की हर दूसरी स्टेट की आबादी से ज्यादा है। यहां आदमियों की क़ूव्वत को इकट्ठा करने यानी मैन पावर मोबोलाइजेशन के जरिये से बहुत कुछ काम हो सकता है। हमें इस क़ूव्वत या शक्ति को इकट्ठा करना चाहिये और श्रमदान के जरिये से काम कराना चाहिए। सरकार ने अभी कुछ दिन हुए २६ जनवरी, सन् १९५३ से एक हफ्ते तक इस ढंग से काम कराया कि मर्दों, औरतों, विद्यार्थियों, बच्चों और छोटे बड़े सब सरकारी कर्मचारियों ने मिलजुल कर बड़े उत्साह, जोश और हृदय के साथ काम किया, फावड़े चलाये और मिट्टी खोदी। ऐसा मालूम होता था कि देश के प्रेम का पूरा पूरा जज़बा काम कर रहा है। सात हज़ार आठ सौ चार मील में नयी सड़कें बनाई गईं और पुरानी की मरम्मत की गई। दो सौ तैंतालीस नये तालाब खुदे और दो सौ पचपन पहले से ज्यादा गहरे किये गये। तीन सौ इक्यावन बंधियां तैयार हुईं। उन्यासी मील गूलें और माइनरें बनीं। पांच सौ छियालिस कुओं पर काम हुआ जिनमें नये भी बनें और पुरानों की मरम्मत हुई। दो सौ सत्तावन पंचायतघरों और पैंतीस पाठशालाओं की इमारतों का काम आरम्भ हुआ। इनके अतिरिक्त सवा लाख गज़ नालियों, बासठ पुलियां, तीन पुल, पांच सौ इक्यासी गांधी चबूतरा, इकसठ हज़ार चार सौ इकहत्तर खाद के और उन्तीस

हज़ार सात सौ सतहत्तर सोकेज पिट्स तैयार हुये। इस ढंग से काम लेने की स्कीम का नाम सेल्फ हेल्प या अपनी मदद आप करो की स्कीम है और इसके जरिये से जो काम कराया गया है, उसकी हिफ़ाज़त और मरम्मत की जिम्मेदारी गांव सभाओं पर रहेगी। इस स्कीम में जबरदस्त क़ूव्वतें छिपी हुई हैं। जिनके जरिये से विशेषकर पंच-वर्षीय योजना में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। हमें इस योजना को अधिक से अधिक सफल और कामयाब बनाना है।

३१—हमारे इस बजट में खर्च करने के लिये एक लाख रुपया औरतों को ऊंचा उठाने के लिये रक्खा गया है। जो स्त्रियां उत्तर प्रदेश में इस समय गिरी और पिछड़ी हुई स्थिति में हैं, उनको ऊंचा उठाने में इसको व्यय किया जायेगा। यह व्यय एक विशेष योजना के द्वारा होगा परन्तु यह योजना जभी सफल होगी जबकि इस प्रदेश के रहने वाले विशेषकर पैसेवाले लोग आर्थिक सहायता दें और इसके काम को आगे बढ़ाने की ग़रज़ से वालिन्टयरी तौर पर काम करने वाले भी मिलें। पब्लिक से इसी में माली इम्दाद का हासिल होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को क़वी उम्मीद है कि यह और दूसरी सहायता भी जिसकी जरूरत होगी, जरूर मिलेगी।

३२—सरकार ने आगामी साल के लिये दस लाख रुपया इस बजट में इसलिये भी रखा है कि जहां तक हो सके बेरोजगारी के दूर करने पर इसको लगाया जाय। सरकार की ओर से जो काम भी इंडस्ट्री, कृषि, शिक्षा संबंधी और दूसरी मदों के लिये किये जाते हैं और पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो काम किये जायेंगे उनसे बेरोजगारी खुदबखुद दूर होती है और होगी परन्तु फिर भी इस पर हर एक मोर्चे से हमला होना जरूरी है इसलिये यह रुपया रखा गया है ताकि खासतौर पर एक स्कीम के द्वारा कृषि और इंडस्ट्री से संबंधित काम पैदा करके उनमें से बेरोजगारों में से कुछ आदमियों को काम पर लगाया जाय।

३३—सिंचाई, सड़कों और खेती के विभागों के ऐसे काम कराने के लिये जो श्रमदान या अपनी मदद आप करने के सिद्धांत पर कराये जा सकते हैं उनके लिये इस बजट में साठ लाख रुपया रखा गया है। पंच-वर्षीय योजना के ऐसे कामों पर जिनका अभी जिक्र किया गया यह रुपया खर्च किया जायगा। सरकार ने इस तजुरबे की बिना पर जो रिपब्लिक वीक में हुआ यह समझा और बजा तौर पर समझा कि इस ढंग से बहुत काम हो सकता है। रिपब्लिक वीक में जो कुछ हुआ है उसको कर के उत्तर प्रदेश ने तमाम भारत के सामने ऐसी मिसाल पेश की है और ऐसा रास्ता दिखाया है जिसको दूसरे मुल्क में मक़बूलियत हासिल हो कर रहेगी। श्रमदान के काम ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिंदा हैं, मुल्कदोस्त हैं, देश का प्रेम रखते हैं और इसको इस आर्थिक गिराव या मालीपस्ती से जहां वह आज है उठा कर सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा सकते हैं। यहांपर मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में २१८ ऐसे कैम्प स्थापित किये गये हैं जहां सरकारी नौकर और नागरिक सिंचाई के माइनर बनाने और उनकी मरम्मत करने में साथ-साथ काम कर रहे हैं।

३४—हिन्दुस्तान में पचपन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इनमें से नौ जिलों में पांच प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में चालू हैं। इनमें खेती के तरीकों को बताने, सोशल शिक्षा, सड़कों, नालियों, स्कूलों, कोआपरेटिव भट्टों और सिंचाई वग़ैरह के सम्बन्ध में काम हो रहा है। इन योजनाओं के लिये इस बजट में इक्यान्वे लाख ब्यासी हजार सात सौ रुपया रखा गया है।

३५—बनारस के जिले में एक जगह है चकिया ग्रान। सरकार ने एक कैम्प कायम कर रखा है जहां दो हजार कैदी काम कर रहे हैं। इस कैम्प में उनको कैदी कहना जुर्म है। अगर कोई कह देता है तो उस पर एक आना जुर्माना होता है। यहां कैदी खुले बंदों फिरते हैं, मैदानों में रहते हैं और चन्द्रप्रभा नदी पर डाकू

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सम्पूर्णानन्द जी होम मिनिस्टर के नाम पर एक बांध बनाया जा रहा है उस पर काम करते हैं और बावजूद हिफाजत और रोक टोक न होने के भागते नहीं और बड़ी दिलचस्पी से काम करते हैं। सरकार उनको शरह मामूल के मुताबिक रोजाना मजदूरी देती है। इस कैम्प की सफलता को देख कर सरकार और कैम्प भी खोलने का इरादा रखती है।

३६—उत्तर, प्रदेश में जेलों की रिफार्म का काम भी जारी है। इस सिद्धान्त पर काम हो रहा है कि जो लोग जेल जायें उनके अन्दर यह बात पैदा की जाय कि वह जुर्म करने को बुरा समझें और उनसे बचें। छट देने में, मुलाकातों और सजाओं के सम्बन्धी कायदों और कैदियों के क्लासों के मुताल्लिक बहुत माकूल किस्म की तब्दीलियां की गई हैं। लखनऊ के सेन्ट्रल जेल को माडल प्रिजन (Model Prison) या नमूने की जेल बना दिया गया है। अब यहां वे कैदी भेजे जाते हैं जिनका चाल-चलन जेल में अच्छा होता है।

३७—उत्तर प्रदेश के ५ साल के प्लान का खर्चा १२१ करोड़ रु० है लेकिन प्लानिंग कमीशन ने इस वक्त तक सिर्फ ९७·८३ करोड़ रु० रखा है। बाकी रुपये की बाबत अभी बात-चीत हो रही है। इस १२१ करोड़ रु० में रिहंद डैम का खर्चा भी, जो ३५ करोड़ रु० है, शामिल नहीं है। यह डैम प्लान में शामिल हो गया है मगर कमीशन से अभी यह तै नहीं हुआ कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार से क्या मिलेगा। प्लान के १२१ करोड़ रु० के खर्च में से ४२ करोड़ रु० १९५२–५३ के अंत तक खर्च हो चुकेंगे और हमारे सामने ८० करोड़ रु० और खर्च करने का सवाल रहेगा। यह एक बड़ी रक़म है और पंच-वर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये इसका खर्च करना जरूरी है। हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट खर्च करने के लिये रुपया आम तौर पर तीन तरीकों से हासिल कर सकती है, १—टैक्स की शक्ल में, २—पब्लिक से कर्जा, ३—केन्द्रीय सरकार से कर्जे की शक्ल में या इमदाद के तौर पर जिसको ग्रान्ट-इन-एड कहते हैं। खर्चे की जरूरत को पूरा करने का एक चौथा तरीका खर्चे को घटा कर रुपया बचाने का भी है।

३८—जहां तक इस चौथी सूरत का ताल्लुक है इस सिद्धान्त को निगाह में रखने की जरूरत है कि सिर्फ उसी खर्चे को बन्द या कम करना चाहिये जो फ़िजूल और ग़ैर-जरूरी हो और जिसके घटाये जाने से एफिशियेन्सी पर कोई असर न पड़ता हो। किसी राज्य का खर्चा घटा नहीं करता बल्कि हमेशा बढ़ता है। अगर बढ़ने की कोई और वजह भी न हो तो जिस कद्र जरूरी स्टाफ रहता है उसकी तनख्वाह का बिल ही मुकर्ररा तरक्कियों की वजह से हर साल बढ़ता रहता है और एक उन्नति करने और विकास पर खर्च करने वाली हुकूमत का खर्चा तो ऐसा होता है कि वह बढ़े बग़ैर रह ही नहीं सकता और उसकी बढ़ोत्तरी को रोकना सख्त मुजिर है फिर भी मैं मानता हूं कि हर सरकार का यह फर्ज है कि फ़िजूल और ग़ैर-जरूरी खर्चा न होने दे और तरक्की को नुक़सान पहुंचाये बग़ैर खर्चे को पूरे कंट्रोल में रखे। यू० पी० की सरकार सन् १९४६ ई० से अब तक बराबर इस काम को करती रही है। उसने एक कमेटी एकोनौमी कमेटी के नाम से बिठला कर खर्चों की जांच कराई और इसके बाद फिर एक रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर मुकर्रर करके उससे भी इस काम को लिया और कमेटी और कमिश्नर की सिफारिशों की बिना पर २ करोड़ ३५ लाख रु० की खर्चे में कमी की। अब भी यू० पी० सरकार के सामने यह उसूल है कि एफीसियन्सी को घटाये बग़ैर जहां तक सम्भव हो खर्चे को कम करे चुनांचे १९५३–५४ के लिये सरकारी महकमों की तरफ से जिस कद्र खर्चों की मांग हुई थी उसको सरकार ने कम किया। हर वर्ष में नये खर्चे का पैदा होना मामूली बात है। बजट के साल के वास्ते

विभाग की ओर से ६ करोड़ ६४ लाख रु० की मांग थी परन्तु कैबिनेट ने इसमें से सिर्फ २ करोड़ ९२ लाख रु० मंजूर किया और बाकी रकम काट दी।

३९—केन्द्रीय सरकार से इमदाद हासिल करने का यह हाल है कि यह सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि भारत के तमाम राज्यों को देती है और उसकी अपनी मुश्किलात भी ह जिनकी वजह से यह आशा करना कि उत्तर प्रदेश वहां से जितना चाहे उतना ही उसको मिल जाये सही नहीं है इसलिये महज केन्द्रीय सरकार की सहायता पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पब्लिक से कर्जों के मिलने का हाल यह है कि आज कल मिलते नहीं। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि न मिलने के कारण क्या हैं इस वक्त उनमें जाने की जरूरत नहीं। तजुर्बे ने बतलाया है कि उनके मिलने में किसी पहले जमाने की तरह अब कामयाबी नहीं होती।

४०—लेकिन जैसा कि मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं पंच-वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये सब से अहम चीज रुपये का प्रबन्ध करना है इतना रुपया सिर्फ टैक्स से या कर्जे से नहीं उगाहा जा सकता है। इसके लिये तो सरकार को उन सबका सहयोग प्राप्त करना होगा जिनकी सेवा करने का हमने संकल्प किया है और वह साधन है, निजी बचतों से लाभ उठाना। अगर कोई ऐसा तरीका निकल आये कि छोटी सी छोटी पूंजी वाला व्यक्ति भी निजी बचत कर सके और हर तबके के लोग उस बचत में भाग ले सकें, तो वास्तव में हमारे राज्य का बड़ा कल्याण होगा। सरकार ने निजी बचत के लिये जो सहूलियतें दी हैं वे हर तबके के लिये समान रूप से लागू होंगी, पर छोटी आमदनी वालों को इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वे अपनी छोटी से छोटी पूंजी को, यानी चार आना तक, सेविंग्स स्टैम्प्स खरीद कर अपने परिवार के लिये बचा सकते हैं और साथ ही बिना कोई खतरा उठाये देश के निर्माण में भाग ले सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग इस दिशा में दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहेंगे। अगर आज कल्याणकारी हुकूमत उन्नति और विकास के लिये अगर कुछ ले तो उसको टैक्स कहना और समझना सही नहीं मालूम होता न उसकी अदायगी से तबीयत को वह नागवारी होनी चाहिये जो आमतौर पर होती है। विकास जिनके लिये किया जाता है उनकी आमदनी को बढ़ाने वाला और आर्थिक स्थिति को ठीक करने वाला होता है। अगर एक राज्य जनता या उसके किसी हिस्से से विकास करने के लिये कुछ ले तो उसके लिये कोई और लफ्ज होना चाहिये। टैक्स के जो माने उसके आरम्भ से समझे जाते रहे हैं उससे विकास के लिये कुछ देना अन्तर रखता है और उसको टैक्स कहा भी जाय तो प्रौसपैरिटी टैक्स कहना चाहिये और उसके देने पर कोई नागवारी नहीं होनी चाहिये। बहरहाल जो कुछ मैंने कहा इसका मतलब यह नहीं कि इसी वक्त कोई टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स लगाने के मामले में तो गवर्नमेंट की एहतियात का यह हाल है कि पिछले बजट पर जो स्पीच हुई थी उसमें डेवलपमेंट लेवी और बेटरमेंट लेवी लगाने के लिये कहा गया था मगर वह लगाई नहीं गई। अगर गवर्नमेंट इस मामले में विशेष एहतियात करना आवश्यक न समझती तो गालिबन पिछली स्पीच के इस एलान या घोषणा पर अमलदरामद हो चुका होता।

४१—जब कि पंचवर्षीय योजना पर व्यय करना हो और रेहन डैम भी बनाना हो और टैक्स नागवार हो, कर्जा मिलता न हो, केन्द्रीय सरकार जरूरत के मुताबिक देती न हो तो फिर क्या सूरत हो जिससे रुपया हासिल किया जाय। क्या महज़ खर्चे के घटाने से? नहीं। मैंने कहा कि सरकार की नजर इस बात पर है कि खर्चा घटाया जाता रहे पहले घटाया भी आइन्दा भी घटाते रहने का पक्का इरादा है मगर आखिर खर्चे के घटाने से कितना रुपया मिल जायगा? शायद यह कहा जाय कि स्टाफ कम होना चाहिये, भारी भारी तनख्वाहें घटनी चाहिये। स्टाफ घटाया भी गया और आगे मुमकिन हो तो और भी घटाया जाय और फ़र्ज़ किया जाय कि बड़ी तनख्वाहें भी घटा दी जायें तो फिर भी क्या मिलेगा। इस स्टेट का

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सैलेरी बिल रुपया का है । इसमें कहां इतनी गुंजाइश है । जहां तक स्टाफ के घटाने का ताल्लुक है जो फिजूल और ज्यादा होगा वही तो घटाया जा सकेगा । यह सदन खर्चे पर जांच-पड़ताल और कंट्रोल के लिये असेम्बली के सदस्यों की एक कमेटी 'एस्टीमेट कमेटी' बना चुका है । इस समिति की जांच मुस्तकिल रहेगी मगर इस कमेटी के बावजूद सरकार ने अगले वर्ष में एक और समिति एकानोमी कमेटी बिठाने के लिये निश्चय किया है जिसके द्वारा खर्चों की और जांच कराना है ताकि जितना भी हो सके उतना और रुपया सरकार को इस स्टेट पर खर्च करने के लिये मिले ।

४२—चूंकि सरकार यह ठान चुकी है कि पंचवर्षीय योजना का काम कराना है पीछे नहीं हटना है, कठिनाइयां आयें तो उनका मुकाबला करना है और जहां तक हो सके बगैर टैक्स लगाये करना है इसलिये जरूरत हुई कि किसी जरिये से विकास पर खर्च करने के लिये कुछ और रुपया हासिल किया जाये । कुछ मुद्दत से इस स्टेट में इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी सिंचाई की शरहों की जांच पड़ताल का काम कर रही है । उसकी सिफारिश पर सरकार ने मौजूदा आबपाशी की शरहों पर ५० फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है और जहां तक आबपाशी की शरहों में जहां जहां कमी ज्यादती थी उनको यकसां कर देना तजवीज किया है । इस तरह ३ करोड़ ३०लाख रु० मिलेगा । इस रुपये से एक फंड डेवलपमेंट फंड के नाम से स्थापित किया गया है जो विकास पर खर्च किया जायगा । यह बढ़ोत्तरी टैक्स नहीं है । ये एक सर्विस का मुआवजा है, एक चीज की जो खरीदने वाले को दी जाती है कीमत और बढ़ जाने पर भी गरां नहीं है । इसके बढ़ाने के कारण ये हैं :

१—सिंचाई की शरहों के ऊपर इस समिति से पहले जिसका उल्लेख अभी किया जा चुका है जो कमेटियां शरहों की जांच-पड़ताल पर बैठी हैं उनकी यह राय रही है कि सिंचाई के बदले में पैदावार का दसवां हिस्सा ले लेना कोई बेजा और गरा बोझा डालना नहीं है ।

२—खाकी जमीन यानी जिसको पानी न मिलता हो और सिंचाई वाली जमीन की उपजाव की काबिलियत में बहुत बड़ा अन्तर है ।

३—नहर या ट्यूब वेल से पानी लेने के मुकाबले में मामूली कुयें या तालाब वगैरह से सिंचाई करने में जो खर्चा होता है उसमें निसबत १:२ या १:३ की है ।

४—१९४८ ई० में जब कि यह समिति बिठाई गयी थी इस वक्त के मुकाबले में जब कि पुरानी शरहें लगाई गयी थीं पैदावार की कीमत तकरीबन पांच गुना थी और जो शरहें पहिले पहल बनाई गई थीं ये कीमतें अब भी उनसे कई गुना ज्यादा हैं ।

४३—जिस समिति ने यह बढ़ोत्तरी तजवीज की है उसने उत्तर प्रदेश का दौरा करके काश्तकारों और एक्सपर्ट्स की शहादतें भी देखीं । इस समिति ने यह भी निश्चय किया है कि शरहों को जो अब तजवीज की गई हैं पैदावार की कीमतों के साथ इस तरह जोर दिया जाय कि पैदावार की कीमतें एक मुकर्रर सीमा से घटें बढ़ें तो इसके साथ २ खुद-बखुद आबपाशी की शरहों में भी घटाव बढ़ाव होता जाये । कमेटी ने काबलियत के साथ सोच विचार करके शरहों की बाबत जो कुछ निश्चय किया वह बहुत माकूल है और उससे कोई ऐसा बोझ पड़ने वाला नहीं है जो बरदाश्त से बाहर हो । जो शरहें अब कायम हुई हैं वह अब भी पैदावार के दसवें हिस्से से काफी कम हैं ।

४४—इस बजट में कोई नये टैक्स तजवीज नहीं किये गये हैं मगर यह मुमकिन है कि वह कुछ चीजों पर सेल्स टैक्स की शरहों में थोड़ा इजाफा करें । इस मद में ३४ लाख रु० की आमदनी बजट में शामिल की गई है । सेल्स टैक्स हमारे यहां दूसरी जगहों के मुकाबिले बहुत कम चीजों पर है और मल्टीपुल पाइन्ट के मुकाबिले में सिंगिल पाइन्ट टैक्स ज्यादा है । हमारे यहां एक्जम्पशन्स बहुत काफी हैं इसलिये

हमारी आमदनी इस टैक्स से सिर्फ ५ करोड़ रुपया सालाना है। दूसरी जगहों मसलन मद्रास में इस टैक्स से १७ करोड़ रुपया सालाना की आमदनी है और बम्बई में १५ करोड़ से ज्यादा है। ऐसी हालत में जाहिर है कि इस इजाफे को किस नजर से देखना चाहिये।

५४—इन दो आमदनियों के अलावा एक तीसरी बढ़ोत्तरी और हुई है जो यह है कि फाइनेन्स कमीशन ने यह सिफारिश की है कि राज्यों को उस आमदनी में से हिस्सा दिया जाय जो केन्द्रीय सरकार को तम्बाकू, दियासलाई और बनस्पति से बने हुये पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से होती है। चुनान्चे उत्तर प्रदेश को ३ करोड़ २१ लाख रुपया मिलेगा। मैं यहाँ साफ़ कर देना चाहता हूं कि इस बात से किसी को यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि हमारी स्टेट को विकास के कामों के लिए जितने रुपये की जरूरत है वह केन्द्रीय सरकार से आई हुई उस रक़म से पूरा हो जायगा। इन असली आंकड़ों को देखकर बिलकुल स्पष्ट हो जाता है जो गवर्नमेंट के उन्नति के विभागों के खर्चों को बताते हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि पंचवर्षीय योजना पहली अप्रैल, सन् १९५१ को आरम्भ हुई है जिसका मतलब यह है कि प्लान दो साल से अमली शक्ल अख्तियार कर रहा है अगर्चे ऐसी सूरत अब पैदा हुई जब कि उसकी रफ्तार रोज ब रोज तेज होती जा रही है कि मालियात पर उसका असर हमको महसूस हो रहा है। बजट लिटरेचर की थोड़ी सी जानकारी हमें बता देगी कि गवर्नमेंट का खर्चा तालीम मेडिकल, स्वास्थ्य, कृषि, पी० डब्ल्यू० डी०, इन्डस्ट्री, लेबर, हरिजन सहायक, पंचायत राज, प्लानिंग वग़ैरह पर १९४५–४६ में सिर्फ १०.८३ करोड़ रुपया था लेकिन विकास के प्रोग्राम की पहली किस्त से १९५०–५१ में २०.२३ करोड़ रुपया हो गया। यह पंचवर्षीय योजना से एक साल पहले ही हो गया था। चालू वर्ष के बोहरराये हुए तखमीनों पर नजर डालिए तो यह २३.८२ करोड़ रुपये तक पहुंचती लेकिन अगर १९५०–५१ से पहले मुक़ाबिला किया जाय तो मालूम होगा कि एक्साइज और जंगलात की प्राप्तियों में तक़रीबन एक करोड़ का घाटा हुआ था। इसका कारण गालिबन आमतौर चीजों की क़ीमत का गिरना, खात्मए जमींदारी का फ़न्ड इकट्ठा होना, गांवों के लोगों का शौक़िया ख़रीद से हाथ उठा लेना और उनमें छोटी रक़मों को रोक लेने की तहरीक पैदा हो जाना थी। दूसरी तरफ़ ग़ल्ले की सप्लाई और राशनिंग स्कीम के सिलसिले में सरकार को नुक़सान हो जाने की वजह से दो करोड़ रुपया उनमें लगाना पड़ा। इस किस्म का और कोई बोझ १९५०–५१ में स्टेट मालिया पर नहीं पड़ा। आमदनी और खर्च जो इन मदों को नजरन्दाज करते हुए जो एक दूसरे को काट देती हैं अगर हम १९५०–५१ के बजट का मुक़ाबिला चालू वर्ष के बजट से करें तो फ़ौरन पता चल जायगा कि १९५०–५१ का बजट मुतावाजिन था। लेकिन चालू वर्ष का बजट साढ़े छः करोड़ रुपये के घाटे में था। फ़ाइनेंस कमीशन की सिफ़ारिश पर जो आमदनी केन्द्रीय एक्साइज की प्राप्तियों से हुई उससे सिर्फ़ सवा तीन करोड़ रुपये की कमी पूरी हो सकी। इससे यह पता चलता है कि चालू वर्ष में केन्द्र से सवा तीन करोड़ रुपये की यह नयी रक़म मिल जाने के बावजूद भी चालू वर्ष के बजट में सवा तीन करोड़ रुपये की कमी क्यों रह गयी। इस कमी को पूरा करने की चूंकि कोई और राह नहीं है इसलिए इस काम के लिए सवा तीन करोड़ रुपये का तबादला रेवेन्यू रिज़र्व फ़न्ड (Revenue Reserve Fund) से किया जायगा।

४६—इस बजट के साल में विकास के विभागों का खर्चा २६,०३ करोड़ रु० (और १९४५–४६ का सिर्फ १०८३ करोड़ रु०) खाने की ग़ल्ले की स्कीमों पर दो करोड़ रुपये का फिर नुकसान हुआ है। जंगलात और एक्साइज की आमदनी में अबकी चालू वर्ष से भी ज्यादा नुक़सान का अन्देशा है। लेकिन इसकी पूर्ति दूसरे टैक्सों और प्राप्तियों और सेल्स टैक्स प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी से हो जायगी। इन तब्दीलियों को नजरन्दाज करते हुए जो एक दूसरे को काट देती हैं बजट का साल बावजूद सवा तीन करोड़ रुपये की कुछ रकम के मुजरा कर लेने के जो केन्द्रीय एक्साइज रेवेन्यू से होगी साढ़े चार करोड़ रुपये की घटौती में जायगा।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

४७—अगर कैपिटल की तरफ़ देखिए तो बहुत जल्द स्पष्ट हो जायगा कि विकास के प्राजेक्ट पर खर्चे की रफ्तार निहायत तेज़ है। बिजली, नहरों, इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इमारतों और सड़कों पर १९४५–४६ का टोटल कैपिटल खर्चा १.४९ करोड़ रुपया था और चालू वर्ष में ११.८७ करोड़ रुपया था, लेकिन आज इस बजट में यह १४.३३ करोड़ रुपया है।

४८—सिंचाई, सेल्स टैक्स और एक्साइज़ की आमदनी के ज़रिए ६ करोड़ ६४ लाख रु० की बढ़ोत्तरी हुई मगर उसमें से सिंचाई की आमदनी डेवलपमेन्ट फन्ड में चली गई जिससे कैपिटल खर्चा होगा और बाक़ी ३ करोड़ ३४ लाख रु० की आमदनी रेवेन्यू में शामिल हुई। इस वक्त बजट में घाटा ४ करोड़ ४२ लाख रु० का है। अगर यह ३ करोड़ ३४ लाख रु० की आमदनी रेवेन्यू में शामिल न होती तो घाटा ७ करोड़ ७६ लाख रु० का होता। और सिंचाई की आमदनी कैपिटल खर्चे को न जाती तो उसमें भी ३ करोड़ ३० लाख रु० का घाटा रहता। इससे जाहिर है कि जो आमदनी बढ़ायी गयी है उसका बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक था इसलिए सरकार पूरी विश्वास रखती है कि इस बढ़ोत्तरी को शिकायत के क़ाबिल नहीं समझा जायगा।

४९—इससे पहले कि मैं खत्म करूं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ़ से सब रहने वालों से अपील करता हूं कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें, न आर्थिक इमदाद करने में दरेग़ करें और न किसी और आवश्यक सहायता में। याद रखना चाहिए कि इस देश के रहने वालों की हिम्मत और हौसलों के सामने पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश को उभारना कोई कठिन काम नहीं है और अगर होता भी तो मैं याद दिलाता कि बहुत प्राचीन समय में यूनानी कहा करते थे कि "आसान काम नहीं बल्कि मुश्किल काम खूबसूरत होते हैं।"

५०—आखिर में मैं श्री बी० जी० राउ, फ़ाइनेंस सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने फ़रायज़ को बहुत तन्दही, ख़ास क़ाब्लियत और दिलचस्पी से अंजाम देते हैं। श्री बी० बी० लाल, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ने भी बड़ी मेहनत, लियाक़त और दिलचस्पी से इस ख़िदमत को अंजाम दिया। मैं उनका और श्री भरत नारायण, डिप्टी सेक्रेटरी, श्री के० एस० गोयल और श्री एन० सी० रे, अन्डर सेक्रेटरियों और खुसूसन श्री केशवदास अन्डर सेक्रेटरी का भी जो वित्त विभाग के बजट सेक्शन के इन्चार्ज हैं, निहायत मशकूर हूं कि उन्होंने बजट की तैयारी में बहुत उम्दा काम किया है। इन साहबान के अलावा फ़ाइनेंस के महकमे के दीगर अफ़सरों व स्टाफ़ व तर्जुमा करने वालों व गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद और लखनऊ के स्टाफ़ को भी इस मौक़े पर नहीं भूल सकता। उन्होंने जो मेहनत की है और तकलीफ़ उठायी है वह भी क़ाबिले शुक्रिया है।

(इसके बाद सदन १२ बज कर २० मिनट पर सोमवार २३ फरवरी, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२१ फरवरी, १९५३।